कानपुर, मंगलवार, 12 मई, 2026
वर्ष: 03, अंक: 117, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.com | swarajindianews | swarajindianews

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड हिमंता बिस्वा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ...>Pg12
उर्सला में डीएम का छापा, दलालों पर कार्रवाई..>Pg03

मूल्य: 2 ₹

नीट-यूजी 2026 रद्दः पेपर लीक की परतें खुलीं तो केंद्र को झुकना पड़ा

22 लाख छात्रों के सपने 'तबाह'

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 आखिरकार रद्द कर दी गई। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 22 से 24 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन परीक्षा के कुछ दिनों बाद ही पेपर लीक और सुनियोजित गड़बड़ियों की परतें खुलनी शुरू हो गईं। मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा निरस्त करने और दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है।

जांच एजेंसियों के शुरुआती इनपुट में सामने आया कि परीक्षा से पहले एक तथाकथित 'गेस पेपर' कई राज्यों में प्रसारित हुआ था, जिसमें वास्तविक प्रश्नपत्र से 100 से अधिक सवाल मेल खाते पाए गए। इसी के बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सबसे पहले मामले की गंभीर जांच शुरू की। जांच के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और यहीं से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ।

सूत्रों के मुताबिक, अब तक 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें कोचिंग नेटवर्क से जुड़े लोग, बिचौलिए और कुछ पूर्व परीक्षा तंत्र से जुड़े संदिग्ध शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि एजेंसियों ने आधिकारिक रूप से सभी नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। जांच में महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया है। केंद्रीय एजेंसियों को शक है कि प्रश्नपत्र की छपाई और पैकेजिंग प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा से समझौता किया गया।

सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आई है कि नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस जांच के दायरे में है, जहां प्रश्नपत्रों की छपाई से जुड़े रिकॉर्ड और कर्मचारियों की भूमिका खंगाली जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जांच एजेंसियां इस एंगल को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। एनटीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि केंद्रीय एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। एजेंसी ने माना कि मौजूदा परीक्षा परिणामों को बरकरार रखना राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ होता।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खास बात यह रही कि परीक्षा से पहले एनटीए ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पेपर लीक दावों को 'फर्जी' बताया था और कहा था कि प्रश्नपत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन परीक्षा के बाद सामने आए तथ्यों ने एजेंसी के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने बड़ा रूप ले लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत को भ्रष्ट व्यवस्था ने कुचल दिया। विपक्ष ने एनटीए को भंग करने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की है।

दिल्ली, जयपुर, पटना, लखनऊ और कोटा समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। छात्रों का कहना है कि वे दोहरी मार झेल रहे हैं—पहले कठिन तैयारी और अब दोबारा परीक्षा का मानसिक दबाव। सोशल मीडिया पर भी #NEETReE&am और #NTAFail जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। सरकार ने साफ किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी और एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। सीबीआई अब यह पता लगाएगी कि पेपर लीक का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला था, किस स्तर पर सेंध लगी और क्या परीक्षा माफिया को अंदरूनी मदद मिली थी।

NEET UG 2026

नासिक प्रिंटिंग प्रेस क्यों जांच में?

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को शक है कि प्रश्नपत्र छपाई और पैकेजिंग चरण में ही लीक हुआ। इसी वजह से महाराष्ट्र और नासिक से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

सबसे पहले किसने पकड़ा मामला?

राजस्थान एसओजी ने सबसे पहले संदिग्ध "गेस पेपर" और वास्तविक प्रश्नपत्र के सवालों में समानता पकड़ी। शुरुआती इनपुट 7-8 मई के बीच मिले, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियों को जानकारी भेजी गई।

कितने लोग जांच के घेरे में?

अब तक 20 से अधिक संदिग्धों को हिरासत या गिरफ्तारी में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। कई राज्यों में कोचिंग नेटवर्क और बिचौलियों पर छापेमारी जारी है।

एनटीए पर सबसे बड़ा सवाल

परीक्षा से पहले एजेंसी ने लीक की खबरों को अफवाह बताया था। बाद में उसी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इससे सुरक्षा प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं।

छात्रों पर क्या असर?

करीब 22 लाख छात्रों को अब फिर से तैयारी करनी होगी। मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और प्रवेश प्रक्रिया में देरी सबसे बड़ी चिंता बन गई है।

टाइमलाइन

- **19 अप्रैल 2026:** सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनलों पर पेपर लीक के दावे वायरल, एनटीए ने इन्हें फर्जी बताया।
- **30 अप्रैल 2026:** एनटीए ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि प्रश्नपत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं।
- **3 मई 2026:** देशभर में नीट-यूजी परीक्षा आयोजित, करीब 22-24 लाख छात्र शामिल हुए।
- **7 मई 2026:** राजस्थान में 'गेस पेपर' और वास्तविक प्रश्नपत्र में समानता की शिकायतें सामने आईं।
- **8 मई 2026:** एनटीए ने मामले को केंद्रीय एजेंसियों के पास भेजा। राजस्थान एसओजी की जांच तेज हुई।
- **10 मई 2026:** कई राज्यों में छापेमारी और संदिग्धों से पूछताछ शुरू। महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया।
- **12 मई 2026:** केंद्र सरकार ने नीट-यूजी 2026 रद्द किया, सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा का ऐलान।

परेड ग्राउंड खाली कराने के विरोध में अमिताभ बाजपेई ने झोंकी ताकत

पुराने बाजार और बिल्डिंग बाईलाज के मुद्दे पर विधायक अमिताभ बाजपेई ने प्रमुख सचिव से की मुलाकात

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने सोमवार को लखनऊ में आवास एवं नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद से मुलाकात कर कानपुर नगर से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विधायक ने परेड मैदान स्थित ऐतिहासिक एवं पारंपरिक हाट बाजार को हटाए जाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह बाजार वर्षों से हजारों दुकानदारों, श्रमिकों और मेहनतकश परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बाजार हटाना जनभावनाओं और सामाजिक हितों के विपरीत होगा।

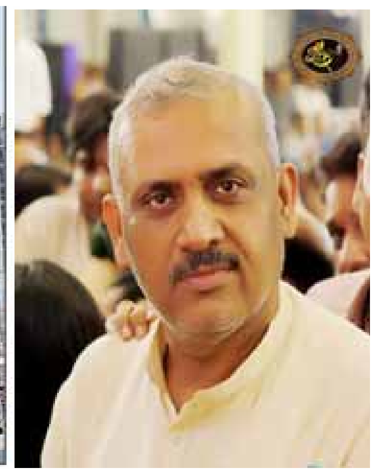

उन्होंने मांग की कि बाजार हटाने संबंधी आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष और संवेदनशील जांच कराई जाए, जिससे गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के रोजगार सुरक्षित रह सकें। विधायक ने नए बिल्डिंग बाईलाज से उत्पन्न समस्याओं को लेकर भी प्रमुख सचिव को विस्तृत पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि कानपुर के पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्र, जैसे मेस्टन रोड, हालसी रोड समेत कई इलाके अंग्रेजी शासनकाल से विकसित हैं, लेकिन उन्हें पुराने बिल्ट-अप एरिया के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि नए बिल्डिंग बाइलाज में 9 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता लागू होने से पुराने इलाकों में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोग अपने पुराने भवनों का पुनर्निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार तक नहीं करा पा रहे हैं। अमिताभ बाजपेई ने मांग की कि दशकों पुराने विकसित क्षेत्रों को पुराने बिल्ट-अप एरिया के रूप में मान्यता दी जाए और नए मॉडल बाईलाज केवल नई विकसित कॉलोनियों एवं क्षेत्रों में लागू किए जाएं।

इसके अलावा उन्होंने आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के तहत अधिसूचित ग्रामों में केडीए द्वारा की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 के तहत अधिसूचित किया गया है, वहां भवन मानचित्र स्वीकृति और निर्माण संबंधी अधिकार परिषद के अधीन होने चाहिए। बावजूद इसके केडीए के हस्तक्षेप से स्थानीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने अधिसूचित क्षेत्रों में केडीए की प्रवर्तन कार्रवाई पर रोक लगाने और संबंधित विभागों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने की मांग की। प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने विधायक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक परीक्षण और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने परेड बाजार प्रकरण में नगर आयुक्त से वार्ता कर जनता के हित में मामले का परीक्षण कराने की बात कही। साथ ही आश्वासन दिया कि पुराने मास्टर प्लान में शामिल बिल्ट-अप एरिया को प्रभावित नहीं किया जाएगा तथा नए मॉडल बाईलाज केवल नए विकसित क्षेत्रों में लागू किए

आरएसएस शताब्दी वर्ष पर केआईटी में प्रमुख जन गोष्ठी हुई आयोजित

शिक्षकों एवं बुद्धिजीवियों से राष्ट्रहित में सकारात्मक, तथ्यपूर्ण एवं रचनात्मक विमर्श को आगे बढ़ाने का आह्वान किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, बुद्धिजीवियों एवं युवाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। गोष्ठी का विषय ÷भारत का वर्तमान परिदृश्य चुनौतियाँ एवं संभावनाएं रहा।

मुख्य वक्ता प्रो. अनूप सिंह, प्राचार्य पीपीएन महाविद्यालय ने कहा कि वर्तमान समय में भ्रामक विमर्श युवाओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों एवं बुद्धिजीवियों से राष्ट्रहित में सकारात्मक, तथ्यपूर्ण एवं रचनात्मक विमर्श को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों को सशक्त बनाकर ही देश को नई दिशा दी जा सकती है।

कार्यक्रम में द्वितीय वक्ता डॉ. प्रियंका सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत ने समरसता को केवल समानता नहीं, बल्कि पारस्परिक सम्मान का आधार बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारों से पहले कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप आधुनिकता के निर्माण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए समाज केंद्रित शोध एवं सतत विकास आधारित नवाचार समय की आवश्यकता हैं।

उन्होंने कहा कि यदि तकनीक के साथ संस्कृति, ज्ञान के साथ चरित्र और प्रतिभा के साथ राष्ट्रभाव जुड़ जाए तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।

कार्यक्रम के अंत में केआईटी के डीन डॉ. आर.के. पांडे ने सभी अतिथियों एवं प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी में आयोजक मयंक पासवान, सुधांशु त्रिपाठी सहित सैकड़ों प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर महिला चढ़ी टावर पर

» पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास ड्रामा होने पर पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। मंगलवार सुबह उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक महिला अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास स्थित टावर पर चढ़ गई। महिला के टावर पर चढ़ते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

बताया जा रहा है कि महिला का प्रेमी राकेश सिंह निहार पास्को एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद है। 11 नवंबर 2025 को थाना सचेंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा था। मंगलवार को पेशी की तारीख पर उसे कोर्ट लाया गया था। इसी दौरान महिला अपनी मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई। महिला का कहना था कि जब तक उसके प्रेमी को जेल से नहीं लाया जाएगा, तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। जानकारी के मुताबिक महिला की मां ने ही नवंबर 2025 में सचेंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान मां ने बेटी पर प्रेमी के खिलाफ गवाही देने का दबाव बनाया, जिससे नाराज होकर महिला ने यह कदम उठाया। सूचना मिलते ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी देर तक चली मशक्कत और समझाने के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

निजीकरण के विरोध में नगर निगम कर्मियों का बिगुल

काला फीता बांध कर्मचारियों ने जताया विरोध, 14 मई की आमसभा में जुटने का आह्वान

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम में निजीकरण के विरोध को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को जोन-1 के कर्मचारियों की बैठक चाचा नेहरू अस्पताल परिसर में आयोजित हुई, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने निजीकरण की प्रक्रिया को कर्मचारी हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग उठाई।

सभा को संबोधित करते हुए समिति के नेताओं ने कहा कि 11 मई से 14 मई तक सभी कर्मचारी काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और नगर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही 14 मई 2026 को मोतीझील मुख्यालय में आयोजित होने वाली विशाल आमसभा में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया।

कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि निजीकरण की नीतियों से स्थायी व आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। सभा के दौरान समिति के नेता हरिओम वाल्मीकि ने आउटसोर्स कर्मचारियों को अब तक वेतन न मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से वार्ता कर तत्काल वेतन भुगतान कराने की मांग की।

इसके बाद समिति के पदाधिकारियों ने मोतीझील मुख्यालय पहुंचकर कर्मचारियों को काला फीता बांधा और नारेबाजी करते हुए आंदोलन को और तेज करने का संदेश दिया।

सभा में जयपाल सिंह, हरिओम वाल्मीकि, रमाकांत मिश्र, धीरज गुप्ता, विनोद रावत, अजीत बाघमार, सुधाकर मिश्र, उस्मान अली शाह, मुन्ना हजारिया, मुकेश वाल्मीकि, पिंटू चौधरी, चमन खन्ना, रामगोपाल चौधरी, राजेंद्र वाल्मीकि, अखिलेश सिंह, बृजलाल भारती, कमरुद्दीन, पवन कौशल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

मरीज की मौत पर अस्पताल में बवाल, चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी घायल

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कल्याणपुर क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में पाइल्स के इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद सोमवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित परिजनों ने शव अस्पताल में रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया। इस दौरान चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई और उनकी वर्दी फाड़ दी गई।

कन्नौज के निजामपुर गढ़िया निवासी गौरव सिंह (35) को पाइल्स की शिकायत पर 9 मई को कल्याणपुर पनकी रोड स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले खून की कमी बताते हुए दो यूनिट ब्लड चढ़ाने की बात कही थी। आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद गौरव की हालत बिगड़ गई और 10 मई की देर रात उसकी मौत हो गई।

मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सोमवार देर शाम बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने

- ➪ कल्याणपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत
- ➪ परिजनों का हंगामा, पुलिस से मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोप

का प्रयास किया तो महिलाएं भड़क उठीं। आरोप है कि भीड़ ने पनकी रोड चौकी प्रभारी विपिन मोरल को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और उनकी वर्दी फाड़ दी। बीच-बचाव करने पहुंचीं महिला दरोगा और कांस्टेबल के साथ भी हाथापाई हुई।

सूचना मिलते ही डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छह महिलाओं और चार पुरुषों को हिरासत में लिया। बाद में महिलाओं को छोड़ दिया गया। परिजन अस्पताल संचालकों और डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने तथा अस्पताल के लाइसेंस की जांच की मांग कर रहे हैं।

उर्सला में डीएम का छापा दलालों पर बड़ी कार्रवाई

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। उर्सला अस्पताल में मरीजों से दलाली और अव्यवस्था की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच मंगलवार सुबह जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा एक्शन लिया। डीएम ने एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार के साथ सुबह करीब 9:30 बजे उर्सला अस्पताल में औचक निरीक्षण कर पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में सक्रिय दो संदिग्ध दलालों को पकड़ा गया, जो मरीजों और तीमारदारों को गुमराह करते हुए निजी जांच और बाहरी इलाज के लिए बहला रहे थे।

डीएम ने मौके पर ही दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि दलालों और बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने सीएमएस उर्सला को निर्देशित किया कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की दलाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। जांच में 22 डॉक्टर सहित कुल 32 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित पाए गए। इस

- ➪ मरीजों को गुमराह करते मिले दो संदिग्ध पकड़े गए, 22 डॉक्टर समेत 32 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित

पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

डीएम ने दवा वितरण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी स्थिति में बाहरी दवाएं न लिखी जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध दवाओं से ही मरीजों का उपचार सुनिश्चित किया जाए, ताकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से अस्पताल प्रशासन में खलबली मची रही, वहीं मरीजों और तीमारदारों ने दलालों के खिलाफ हुई कार्रवाई का स्वागत किया।

केडीए में दलालों की घुसपैठ से व्यवस्था पर सवाल !

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

फाइलों में हेराफेरी, अवैध वसूली और सुरक्षा व्यवस्था पर मंडरा रहा बड़ा खतरा

अधिवक्ताओं की आड़ में सक्रिय गैंग पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने के भी आरोप लगते रहे हैं

कानपुर।कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में दलालों की बढ़ती घुसपैठ अब प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल बनती जा रही है। केडीए मुख्यालय के बाहर और परिसर के आसपास सक्रिय कथित दलालों का नेटवर्क न सिर्फ आम लोगों को गुमराह कर रहा है, बल्कि फाइलों में हेराफेरी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं।सूत्रों के मुताबिक केडीए परिसर के बाहर वर्षों से टीनशेड और अस्थायी दुकानों की आड़ में दलालों का जमावड़ा बना हुआ है। यहां बैठने वाले कई लोग खुद को अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक या सुविधा प्रदाता बताकर आम लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। आरोप है कि ये लोग केडीए के भीतर तक पहुंच बनाकर फाइलों की गतिविधियों की जानकारी लेते हैं और नियमों के विपरीत कार्य कराने का दावा करते हैं।

02
कानपुर-सिटी
स्वराज इंडिया
केडीए के बगल में अधिवक्ताओं की आड़ में दलालों का कब्जा

FOLLOW UP

स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन मानचित्र, नामांतरण, अवैध निर्माण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और संपत्ति संबंधी मामलों में दलाल सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कई मामलों में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी विभागों को गुमराह करने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे केडीए की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

सबसे चिंताजनक पहलू सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। केडीए परिसर में बैंक सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित हैं, लेकिन मुख्य दीवार से सटी अवैध दुकानों और टीनशेडों के कारण सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि बाहरी लोगों की लगातार आवाजाही से संवेदनशील अभिलेखों और कार्यालय व्यवस्था पर खतरा बना रहता है।

मामले को लेकर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतें भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय कई मामलों को दबाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, शिकायत करने वालों को धमकी भरे फोन आने की बातें भी सामने आई हैं।शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने वाला केडीए अपने मुख्यालय के आसपास फैले कथित दलाल तंत्र और अवैध कब्जों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है।

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि केडीए परिसर और उसके आसपास की दुकानों का सत्यापन कराया जाए, अवैध कब्जों को हटाया जाए तथा दलालों के नेटवर्क की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और प्राधिकरण की साख बचाई जा सके।

रोड स्वीपिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कवायद तेज

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ चंद्र शेखर सिंह ने की समीक्षा बैठक

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर की प्रमुख सड़कों पर सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के लिए नगर निगम ने रोड स्वीपिंग कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा कार्यालय कक्ष में विशेष बैठक आयोजित कर शहर में रोड स्वीपर मशीनों के माध्यम से चल रहे सफाई कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में नगर निगम सीमा क्षेत्र के मुख्य मार्गों, डिवाइडरों और सड़क किनारों की साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने रोड स्वीपिंग कार्य में आ रही समस्याओं एवं सुधार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने निर्देश दिए कि शहरवासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए रोड स्वीपिंग कार्य को और अधिक व्यवस्थित एवं सुचारु ढंग से संचालित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों की नियमित सफाई से शहर की सुंदरता के साथ-साथ स्वच्छता व्यवस्था भी मजबूत होगी।बैठक में समस्त जोनल स्वच्छता अधिकारी, मेसर्स जेकेओ कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि तथा कंपनी के डिपो इंचार्ज रफुल रहमान मौजूद रहे।

ई-ऑफिस अपडेट बना कर्मचारियों के लिए मुसीबत, राज्य कर विभाग में वेतन भुगतान रोका गया

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। राज्य कर विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली के तहत आईडी अपडेट की प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। विभागीय कर्मचारियों को 11 मई तक वेतन का भुगतान नहीं हो सका, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। वेतन रुकने से कर्मचारियों के सामने घरेलू और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री एवं जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने बताया कि वेतन भुगतान न होने से कर्मचारियों के मकान किराया, बच्चों की फीस, बिजली बिल, ईएमआई, बीमा किस्त तथा अन्य घरेलू खर्च प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों को अनावश्यक मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कर्मचारियों का वेतन न रोके जाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं विभागीय अधिकारी शासन के आदेशों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं।राजा भरत अवस्थी ने कहा कि यदि जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारियों में आक्रोश और बढ़ सकता है।

कर्मचारी नेता राजा भरत अवस्थी ने उठाया मामला

कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।

सम्पादकीय

नागरिकों संग शासन-प्रशासन भी हो अनुशासित

खाड़ी युद्ध से उपजे हालात व बाधित वैश्विक आपूर्ति शृंखला के बीच प्रधानमंत्री का ईंधन के उपयोग व सोने की खरीद में संयम बरतने का आह्वान निस्संदेह, वक्त की जरूरत है। लेकिन तेलंगाना के बाद बडोदरा से दूसरी बार उनके राष्ट्र को संबोधन व इसके समय को लेकर सवाल भी उठे हैं। निस्संदेह, हालात काफी दिनों से चुनौतीपूर्ण बने हैं, रुपये में तेज गिरावट व महंगे कच्चे तेल के आयात की वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी दबाव में रहा है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि इस घोषणा के लिये विधानसभा चुनाव परिणामों का इंतजार क्यों किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता शीर्ष से किया गया आह्वान कई बार देश में असुरक्षाबोध पैदा करता है, जिसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। दरअसल, इससे कृत्रिम संकट पैदा करने वाले तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। इससे चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें दो राय नहीं कि देश बड़ी मात्रा में कच्चा तेल व सोना आयात करता है। जाहिर बात है जब इनकी वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो इन दोनों के कारण भारी दबाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। निस्संदेह, विषम वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन की बचत, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना चुनौतियों से मुकाबले के लिये समझदारी भरे उपाय हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले डेढ़ माह में सरकार विधानसभा चुनावों में व्यस्त रही। इस दौरान आर्थिक प्रबंधन का मुद्दा हाशिये पर चला गया। अब इन चुनौतियों से मुकाबले के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों से विदेशों में शादियां टालने, सोना खरीदने से बचने के लिये कहना बताता है कि रुपये में तेज गिरावट से सरकार चिंतित है। कहा जा रहा है कि बार-बार अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा करने वाली सरकार को जनता से व्यवहार में संयम बरतने का आग्रह करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी।

दरअसल, आशंका यह भी है कि इन कदमों के ऐसे भी नतीजे निकल सकते हैं,जिनकी उम्मीद न की गई हो। निर्विवाद रूप से सोना भारतीय संस्कारों में है। वहीं भारत में आभूषण उद्योग लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है। ऐसे में सोने की खरीद में गिरावट से संपन्न निवेशकों के मुकाबले श्रमिकों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर वर्क-फ्रॉम होम की नीति, काम करने वालों के बड़े तबके के लिए व्यावहारिक नहीं है। निस्संदेह, किसी भी आसन्न संकट में नागरिकों की जिम्मेदारी मायने रखती है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रियों के कारों के काफिलों पर भी अंकुश लगेगा.. क्या शासन प्रशासन की शाहखर्ची पर लगाम लगेगी...। यदि ऐसा नहीं होता तो जनता की स्वतःस्फूर्त पहल प्रभावित होगी। वैसे भी नागरिक जिम्मेदारी एक हद तक तो प्रभावी हो सकती है,लेकिन वह किसी आपातकालीन योजना का विकल्प नहीं हो सकती। सरकार को भी अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत है। जहां तक सोने की खरीद पर संयम का सवाल है तो उससे देश में गहरा भावनात्मक लगाव जुड़ा रहा है। सोना हमारी संस्कृति, परंपरा, बचत और पारिवारिक समारोहों में गहरे तक शामिल रहा है। लेकिन सदियों से सम्मोहित करते सोने का आयात विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा असर डालता है। ऐसे में राष्ट्र हितों के मद्देनजर जीवन यापन करना, राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने जैसा है। विगत में कई बार जब देश पर संकट आया तो लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिये सोना तक दान किया।

आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल छह सौ से सात सौ टन सोना आयात होता है, लेकिन निर्यात का प्रतिशत ना के बराबर है।

भारतीय सैन्य सेवा की प्रतिज्ञा और अनुबंध के मायने

निरंजन भंडारी

भारतीय सेना अपने लिए अलग ढांचे की हकदार है। सैनिक शपथ लेकर राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण चुनता है। जहां उसकी पहचान वर्दी ही होती है। 'जेनरेशन ज़ेड' बड़े मकसद से सेना को चुन रही है। यह सैनिक बनने का जज्बा है। जरूरी है सैन्य शपथ लेने वालों के अनुरूप नीतियां बनें।कोहिमा युद्ध स्मारक पर एक सादा-सा शिलालेख है, जिसको भारतीय भूमि पर लड़े गए भीषणतम युद्धों में एक की यादगार में लगाया था, इस पर उकेरी पंक्ति है : 'जब तुम घर लौटोगे, तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना कि तुम्हारे कल के लिए, हमने अपना आज दिया'।

यह कोई नारा नहीं, सच्चाई की दास्तां है।बहुत से लोगों को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान का तो पता है, जो तीन महाद्वीपों में लड़ी गई थीं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की एक लड़ाई भारतीय भूमि पर भी लड़ी गई। कोहिमा की लड़ाई, जिसे 'भूला-बिसरा युद्ध' भी कहा गया था , आज दुनिया भर के सैन्य इतिहासकार इसे द्वितीय महायुद्ध के बेहतरीन सैन्य अभियानों में से एक के रूप में मानते हैं। वर्ष 1944 में, पहाड़ी की चोटी पर -जो बाद में कोहिमा की लड़ाई का पर्याय बन गयी-सैनिक इतनी नज़दीकी से लड़े कि आमने-सामने की खंदकों के बीच पड़ता टेनिस कोर्ट ही युद्ध का मैदान बन गया। वर्षों बाद वह शिलालेख न केवल प्राप्त विजय के बारे में है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी चीज़ का प्रतीक बन गया – अपने आप में सैन्य सेवा की प्रकृति का। इसने कुछ नया नहीं रचा। यह तो एक प्राचीन विरासत पर मुहर लगाता है- भारतीय सैनिक की सभ्यतागत विरासत पर।ऐतिहासिक रूप से, भारतीय सैनिक सदा बलिदान देने के लिए स्वेच्छा से अग्रणी रहा है। यह खासियत मायने रखती है। आज इसका महत्व पहले से कहीं अधिक है। दूसरों के उलट, सैनिक अपनी मर्ज़ी से नौकरी नहीं छोड़ सकता, न यूनियन बना सकता है, न ही तबादले के खिलाफ़ मुक़दमा कर सकता है, और न ही वह किसी ऐसे आदेश को मानने से इनकार कर सकता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती हो। यह महज एक जीवनशैली चुनने का मामला नहीं। जो हक अन्य नागरिकों के पास होते हैं, यह उनका कानूनन समर्पण करना है। गणतंत्र का यह एकमात्र पेशा है, जहां संविधान केवल वह चीज़ नहीं जिसके तहत आप जीते हैं, बल्कि यह वह चीज़ है जिसके लिए आपको अपनी जान देने का आदेश भी दिया जा सकता है। इस शपथ को उसी ढांचे के अधीन रखना जिसमें सामान्य 'दायित्व-आधारित सेवा' परिभाषित की जाती है, न केवल प्रशासनिक लापरवाही, बल्कि एक 'श्रेणीगत त्रुटि' भी होगी।लेकिन सैनिक का दायित्व शरीर से आगे उसके 'स्व' में समा जाता है। वह उन सब चीज़ों को छोड़ देता है, जो बतौर नागरिक जीवन में उसको अलग पहचान देती हैं। मसलन, भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनीतिक पसंद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं-ये सभी इंसान के तौर पर उसका हिस्सा तो बनी रहती हैं, लेकिन उस विस्तारित मानसिकता पर हावी नहीं हो पातीं, जिसमें वह स्वयं को ढाल चुका होता है। यह बदलाव क्रियान्वयन से जुड़ा है। गोलीबारी के बीच पहचान प्रबंधन की खातिर एकजुटता खारिज नहीं हो सकती। रेजिमेंट काम कर पाती है क्योंकि वर्दी 'स्व' की जगह कुछ बड़ा स्थापित कर देती है। पहचान अहलदा रखनी पड़ती है क्योंकि ज़िंदा रहने, कमान और भरोसे के लिए यह करना जरूरी है।अंततः सैनिक हरेक नागरिक का सैनिक बन जाता है। जब वह बाढ़, आग या हिंसा-दंगे के बाद राहत पहुंचाने किसी के द्वार पहुंचता है, तो वह उससे उसकी जाति नहीं पूछता। न ही सैनिक अपनी जाति बताता है। भारतीय समाज को बांटने वाली चीज़ें उस दहलीज पर पहुंचते ही मिट जाती हैं। वह निजी पहचान रूपी टुकड़े को वहां पहुंचने से बहुत पहले तज चुका होता है। सेवा चयन बोर्ड में भर्ती के वक्त। पासिंग-आउट परेड में। पहली बार जब वह वर्दी पहनता और समझ बन जाती है कि यह उससे क्या चाहती है। नौकरी के लिए यह त्याग वक्ती नहीं। सेवा का सबसे गहरा रूप है। दरवाज़े पर पहुंचा सैनिक बतौर एक देश आया है।

राजनीतिक विमर्श का जरिया बनी झालमुढ़ी वालों के फिरेंगे दिन

विशेषकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुढ़ी या मुड़ी तैयार की जाती है। इसके लिए पहले धान को उबाला जाता है, फिर उसे सुखाकर जो चावल निकाला जाता है, उसे भूनने के बाद मुढ़ी या मुड़ी का रूप मिलता है। इस तरह से कह सकते हैं कि मुढ़ी या मुड़ी सेला चावल का भुना हुआ रूप है।पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी की अगुआई में राज्य में नई सरकार बन चुकी है।

ममता बनर्जी की सरकार इतिहास के पन्नों में सिमट गई है। यूं तो हर चुनाव अभियान के साथ तमाम घटनाएं इतिहास में समाती रहती हैं। उनमें से कुछ का प्रभाव बरसों तक रहता है। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव अभियान में एक घटना ऐसी घटी, जिसने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के वोटरों पर अमिट छाप छोड़ी, बल्कि बांग्ला खान-पान और संस्कृति से उन लोगों को भी परिचित करा दिया, जो उससे अब तक सर्वथा अपरिचित थे। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, समूचे बिहार, झारखंड और उड़ीसा में झालमुढ़ी खानपान का अभिन्न अंग है। झालमुढ़ी में दो शब्द हैं। पहला शब्द है झाल, जिसका मतलब होता है तीखा..ऐसा तीखापन, जिसका असर सिर्फ जुबान पर ही नहीं महसूस हो, बल्कि जुबान की सिसियाहट के साथ नाक के रास्ते भी हल्की झलन का अहसास है। इस शब्द के मूल में है मुढ़ी, जिसे कहीं मुड़ी तो कहीं मुरमुरा तो कहीं मुर्ही कहा जाता है। इसमें प्याज, टमाटर, नमकीन, हरी मिर्च, सरसों तेल, नमक और भुना जीरा आदि डालकर जो मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे झालमुढ़ी या झालमुड़ी कहा जाता है। इसी झालमुढ़ी को झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में 19 अप्रैल के दिन चुनाव प्रचार के बीच सड़क पर उतर कर मात्र दस रूपए में खरीदकर जब प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद महिलाओं-बच्चों के साथ मिलकर खाया था। इसके साथ ही झालमुढ़ी इंटरनेट सर्च की दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गई।

झालमुढ़ी में कई बार भुने हुए चने

भी मिलाए जाते हैं तो कई बार भीगे हुए कच्चे चने तो कई बार उस चने से बनी घुघनी। जिन्हें घुघुनी के बारे में पता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि भीगे हुए चने को जीरा, हरी मिर्च के सरसों तेल में छौंक लगाने के बाद सूखा और कई बार प्याज-टमाटर आदि मिलाकर मसालों को साथ भी पकाया जाता है। पश्चिम बंगाल ही क्यों, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मुढ़ी को विशेषकर शाम की चाय के वक्त खाया जाता है। इन इलाकों के स्कूलों, कॉलेजों के बाहर, कचहरियों में स्टेशन के सामने झालमुढ़ी के ठेले और खोमचे खूब दिख जाएंगे। विशेषकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुढ़ी या मुड़ी तैयार की जाती है। इसके लिए पहले धान को उबाला जाता है, फिर उसे सुखाकर जो चावल निकाला जाता है, उसे भूनने के बाद मुढ़ी या मुड़ी का रूप मिलता है। इस तरह से कह सकते हैं कि मुढ़ी या मुड़ी सेला चावल का भुना हुआ रूप है। पश्चिम बंगाल और मिथिलांचल में तो मुढ़ी को पकौड़े के साथ भी खाया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो इसे आलूचप के साथ विशेष रूप में पसंद किया जाता है। अब सवाल उठ सकता है कि आलूचप क्या होता है। दरअसल उबले आलू को मसलकर उसमें नमक, मसाले आदि मिलाकर उसकी टिक्की को बनाया जाता है। फिर उसे बेसन में डुबोकर छाना जाता है। इसे ही आलूचप कहा जाता है। वैसे आलूचप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में खूब प्रचलित है। विशेषकर शाम की चाय के वक्त। राजनीतिक, चुनावी आदि चर्चाओं में चाय के साथ सहज उपलब्ध झालमुढ़ी ही होती है। कई बार सिर्फ मुढ़ी भी खाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शादी-विवाह मुंडन-जनेऊ के हल्दी और मंडप बनाने के दिन विशेषरूप से लोगों को सिर्फ मुढ़ी मिठाई या गुड़ के साथ नाश्ते में दी जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कोलकाता के एक मैदान पर ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो के संग झालमुढ़ी खाया था। इसके जरिए उन्होंने अपनी विजय, भाजपा से बेफिक्री और अपने लोगों को संदेश दिया था। उन्नीस अप्रैल को झारग्राम में झालमुढ़ी खरीदते वक्त पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी को यह पता था कि नहीं, लेकिन उन्होंने इसके जरिए इतिहास रच दिया। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े संचारक यानी कम्युनिकेटर थे। प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े संचारक यानी कम्युनिकेटर हैं।

मात्र दस रूपए की झालमुढ़ी के जरिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के आम लोगों के दिलों तक जगह बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी का संदेश सीधे हर घर तक पहुंचा दिया।

पंचायत भवन के प्रस्ताव पर गरमाई बैठक, जूता-लात की नौबत

जमीन चयन को लेकर दो गुट आमने-सामने, लेखपाल व प्रधान ने संभाला माहौल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। पलिया बुजुर्ग ग्राम पंचायत में नए डिजिटल पंचायत भवन के निर्माण को लेकर बुलाई गई बैठक हंगामेदार हो गई। पंचायत भवन के लिए जमीन चयन को लेकर ग्रामीण दो गुटों में बंट गए और कहासुनी बढ़ते-बढ़ते भिड़ंत की नौबत आ गई। स्थिति बिगड़ती देख मौजूद लेखपाल व ग्राम प्रधान ने दोनों पक्षों को शांत कराया।

प्राथमिक विद्यालय पलिया बुजुर्ग में सोमवार को आयोजित बैठक में लेखपाल सुनील चौधरी और ग्राम प्रधान सुजीत यादव मौजूद थे। पंचायत भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन तलाशने को लेकर ग्रामीणों से सुझाव मांगे गए। कई स्थान प्रस्तावित हुए, लेकिन पर्याप्त भूमि

उपलब्ध न होने पर ग्राम प्रधान की ओर से जमुनिया पुरवा में पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर कुछ ग्रामीण सहमत हुए, जबकि कई लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। बैठक में कई बार जूता लात की नौबत आते आते रही।

पुराने पंचायत भवन को विकसित करने की मांग

गांव में प्रधानी के दावेदार डॉ. आशीष समेत कई ग्रामीणों ने पुराने पंचायत भवन को ही विकसित कर डिजिटल पंचायत भवन बनाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि मौजूदा पंचायत भवन गांव के बीच स्थित है और सभी के लिए सुविधाजनक है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अपने घर के पास पंचायत भवन बनवाना चाहते हैं और इसके लिए घर-घर जाकर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। हालांकि प्रधान समर्थकों ने आरोपों को निराधार बताया।

किसान के तंज पर गूंजे ठहाके

तीसरे दिन तकरीबन तीन घंटे चली बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसी दौरान एक किसान ने तंज कसते हुए कहा,रात मां टार्च लेकर ढूंढियो का जमीन। किसान की बात सुनकर बैठक में मौजूद लोग हंस पड़े। बाद में ग्राम प्रधान ने पलिया में जमीन न मिलने की बात कहते हुए लेखपाल से जमुनिया नेवादा के लिए प्रस्ताव तैयार कराया, जिस पर अधिकांश सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि पंचायत भवन निर्माण के प्रस्ताव पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। इसी बीच एक किसान ने पंचायत भवन दूसरे गांव में न बनने देने के लिए करीब छह बिस्वा जमीन देने की पेशकश की, लेकिन उसकी शर्तों पर सहमति नहीं बन सकी।

डिवाइडर पर चढ़कर ट्रक के नाले में पलटते ही मची चीख-पुकार

- चौबेपुर के तातियागंज में भोर पहर हुआ हादसा
- मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग भागे, चालक सुरक्षित

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर मंगलवार की भोर तातियागंज इलाके में बड़ा हादसा टल गया। कानपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड किनारे नाले में पलट गया। हादसे के समय आसपास मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि चालक समय रहते ट्रक से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भोर के समय हाईवे किनारे लोग टहल रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक अचानक डगमगाने लगा। कुछ ही सेकेंड में उसका अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया और ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। ट्रक को अपनी ओर आता देख आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण वाहन से नियंत्रण हट गया था। ट्रक पलटने से पहले चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए छलांग लगा दी। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई।

चौबेपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त ट्रक को हटवाने की व्यवस्था कराई, ताकि यातायात सामान्य हो सके। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उड़ती धूल को समझ बैठे धुआं, ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

शिवराजपुर/बिल्हौर(कानपुर)। कानपुर से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन में सोमवार शाम आग लगने की अफवाह फैलने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। बर्राजपुर रेलवे स्टेशन से पहले पकरा क्रॉसिंग के पास किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकते ही कई यात्री नीचे उतर गए, जबकि कुछ लोग चलती ट्रेन से कूद पड़े। बाद में जांच में आग लगने की सूचना पूरी तरह अफवाह निकली।

बताया गया कि कानपुर-फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर नई गिट्टी डाले जाने के कारण ट्रेन गुजरने पर धूल उड़ रही थी। शाम करीब चार बजे पकरा क्रॉसिंग के पास ट्रेन पहुंची तो ट्रैक किनारे उठी धूल को कुछ यात्रियों ने धुआं समझ लिया। देखते ही देखते ट्रेन में आग लगने की चर्चा फैल गई और दहशत में किसी ने

- चेन पुलिंग कर रोकी गई पैसेंजर ट्रेन

चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन रुकने से पहले ही यात्री नीचे उतरने लगे। करीब दस मिनट बाद जब कोई खतरा सामने नहीं आया तो ट्रेन को दोबारा रवाना कर दिया गया।

इस दौरान जो यात्री नीचे उतर चुके थे, वे दोबारा ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कई लोग गेट पकड़कर लटकते नजर आए, जबकि कुछ यात्री चढ़ने के दौरान गिर पड़े। महिलाओं में सामान ट्रेन में छूट जाने को लेकर ज्यादा अफरा-तफरी दिखाई दी। सूचना पर शिवराजपुर थाना प्रभारी अमित सिंह मौके पर पहुंचे और रेलवे कर्मचारियों व स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

पुलिस जांच में सामने आया कि ट्रेन में आग लगने जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। अफवाह के चलते यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक किनारे उड़ रही धूल को धुआं समझ लेने से भ्रम की स्थिति बनी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चेन पुलिंग किए जाने की भी जानकारी मिली है। मामले की जांच कर अफवाह फैलाने वालों की तलाश की जा रही है। स्टेशन मास्टर रामचरित्र ने बताया कि उन्हें केवल चेन पुलिंग के कारण ट्रेन रुकने की सूचना मिली थी। आग लगने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। रेलवे स्तर पर पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

सामूहिक विवाह योजना में बड़ा खेल, पहले से शादीशुदा निकलीं 76 बेटियां

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने वाले 76 श्रमिक अपात्र पाए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि जिन बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता मांगी गई थी, उनमें से कई की शादी पहले ही हो चुकी थी।

श्रमिक अमरनाथ कुरील ने बेटी महिमा की शादी के लिए 14 मई को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में आवेदन किया था। जांच के दौरान पता चला कि महिमा का विवाह 18 अप्रैल को ही संपन्न हो चुका है। इसी

श्रम विभाग की जांच में खुलासा, शादी हो चुकी बेटियों के नाम पर मांगी जा रही थी लाखों की सहायता

तरह श्रमिक जयपाल ने बेटी गोल्डी के विवाह के लिए आवेदन किया, लेकिन पड़ताल में सामने आया कि गोल्डी की शादी 13 मार्च को हो चुकी थी।श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह सिर्फ दो उदाहरण हैं। सामूहिक विवाह योजना के लिए कुल 177 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच श्रम निरीक्षकों से कराई गई। जांच में 76 आवेदन अपात्र पाए गए। इनमें अधिकांश मामलों में बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी थी।श्रम विभाग इस योजना के तहत बेटी की शादी पर 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देता है, जबकि 15 हजार रुपये कपड़ों और विवाह आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। इससे पहले यह सहायता राशि 65 हजार रुपये थी।

इस बार सामूहिक विवाह समारोह 14 मई को कानपुर के पांडु नगर स्थित आईटीआई ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कानपुर मंडल के छह जिलों कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया और इटावा के 101 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे, जबकि राज्यमंत्री मनोहर लाल को भी आमंत्रित किया गया है।सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने बताया कि किसी भी योजना का लाभ देने से पहले आवेदनों की जांच अनिवार्य रूप से कराई जाती है। जांच में अपात्र पाए गए लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।गौरतलब है कि कन्या सहायता योजना पहले भी विवादों में रह चुकी है। जनवरी 2024 में विभागीय अधिकारी की आईडी का इस्तेमाल कर वेब पोर्टल पर लॉगिन करके 201 अपात्र लोगों को 10.78 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया था। उस प्रकरण की जांच भी अभी जारी है।

24 घंटे में तीन कत्ल करने वाला ‘साइको किलर’ एनकाउंटर में ढेर

ट्रेन और अस्पताल में ताबड़तोड़ हत्याओं से दहला चंदौली, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया पूर्व सैनिक गुरप्रीत

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

चंदौली। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 24 घंटे के भीतर तीन लोगों की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले कथित सीरियल किलर गुरप्रीत को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पंजाब के अमृतसर निवासी गुरप्रीत पर अलग-अलग ट्रेनों और एक निजी अस्पताल में घुसकर तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।

पुलिस के मुताबिक आरोपी सेना का रिटायर्ड जवान था और हाल ही में नौकरी छूटने के बाद मानसिक तनाव में चल रहा था।पुलिस जांच में सामने आया कि गुरप्रीत वर्ष 2021 में सेना से रिटायर हुआ था। इसके बाद वह बिहार के आरा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, लेकिन शराब की लत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी छूटने के बाद वह गहरे तनाव और गुस्से में रहने लगा था। पुलिस का दावा है कि इसी मानसिक स्थिति में उसने लगातार तीन हत्याओं को अंजाम दिया।पहली वारदात रविवार सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से दिलदारनगर जा रही पैसेंजर ट्रेन में हुई। सकलडीहा रेलवे स्टेशन के पास जमानिया निवासी मंगरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। इस घटना की जांच चल ही रही थी कि दूसरी वारदात सामने आ गई। रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात सियालदह-जम्मू तवी एक्सप्रेस में गया से लखनऊ जा रहे दिनेश साहू की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।इन दोनों घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस को सोमवार सुबह तीसरी हत्या की सूचना मिली।अलीनगर थाना क्षेत्र के कमलापुर गांव स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही बिहार के भभुआ निवासी लक्ष्मीना देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस बार आरोपी भाग नहीं सका। वारदात के बाद ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़

लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार रिक्रिएशन के दौरान गुरप्रीत ने मौका पाकर एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह मारा गया।पुलिस का कहना है कि जिन तीन लोगों की हत्या की गई, उनका आरोपी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। शुरुआती जांच में यह मामला मानसिक अस्थिरता और हिंसक प्रवृत्ति से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। लगातार हुई इन सनसनीखेज हत्याओं से चंदौली समेत पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था।

मुठभेड़ में दबोचा गया 25 हजार का इनामी धर्मवीर

» 2022 के अपहरण व हत्या मामले में फरार हिस्ट्रीशीटर पुलिस फायरिंग में घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कन्नौज। छिबरामऊ थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर सागर उर्फ धर्मवीर उर्फ धर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया है। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, तीन जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है।पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि धर्मवीर वर्ष 2022 से अपहरण और हत्या के मामले में फरार चल रहा था। 12 अक्टूबर 2022 को संगीता देवी ने थाना छिबरामऊ में विजेंद्र कुमार, विवेक, आदेश और सागर उर्फ धर्मवीर के खिलाफ पति राहुल के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके चार दिन बाद राहुल का शव बरामद होने पर मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाई गई थी। मामले में विजेंद्र और विवेक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, जबकि धर्मवीर लगातार फरार था। सोमवार सुबह फर्रुखाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया और मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट और गैंगस्टर समेत करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं।

41 साल बाद गैंगरेप केस में तीन दोषी बरी हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

एफआईआर में देरी और मेडिकल सबूतों की कमी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा- अभियोजन की कहानी भरोसेमंद नहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1983 के गैंगरेप मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों को 41 साल बाद बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने संदेह का लाभ देते हुए कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करने में बिना ठोस कारण देरी हुई और मेडिकल साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं होती।हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत द्वारा मई 1984 में सुनाए गए फैसले को रद्द करते हुए हेतराम, शंकर और भूदत्त को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने तीनों को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी।मामले के अनुसार, 9 मई 1983 को शिकायतकर्ता जब बकरियां चराकर घर लौटा तो उसने घर अंदर से बंद पाया।दीवार फांदकर अंदर जाने पर उसने तीन लोगों को भागते देखा। उसकी पत्नी, जो उस समय सात माह की गर्भवती थी, ने आरोप लगाया था कि चार लोगों ने चाकू की नोक पर करीब एक घंटे तक उसके साथ गैंगरेप किया। हालांकि घटना के पांच दिन बाद 14 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में चार आरोपियों द्वारा रेप का जिक्र है, लेकिन नाम केवल तीन लोगों के दर्ज किए गए। अदालत ने इसे अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर विरोधाभास माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सात माह की गर्भवती महिला के साथ चार लोगों ने एक घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया होता तो गंभीर चिकित्सकीय स्थिति पैदा होना स्वाभाविक था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई पुष्टि नहीं मिली।अदालत ने पाया कि घटना के पांच दिन बाद तैयार की गई मेडिको-लीगल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार की चोट दर्ज नहीं थी।पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी गर्भावस्था सामान्य बताई गई। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों की अपराध में प्रत्यक्ष संलिप्तता थी।हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘लल्लीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य’ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म मामलों में चोट का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब गवाही की विश्वसनीयता संदिग्ध हो तो मेडिकल साक्ष्य अहम हो जाते हैं। अदालत ने पीड़िता के उस दावे को भी स्वीकार नहीं किया जिसमें उसने कहा था कि टूटी चूड़ियों से उसके हाथों में चोट लगी और खून बहा था। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को घटनास्थल से टूटी चूड़ियां नहीं मिलीं और डॉक्टर ने भी ऐसी किसी चोट का जिक्र नहीं किया।इन सभी तथ्यों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।

बारा गांव में गंदगी देख डीपीआरओ नाराज, भेजी टीम

स्वराज इंडिया की खबर का बड़ा असर, डीपीआरओ विकास पटेल ने लिया संज्ञान

25 अप्रैल को प्रमुखता से प्रकाशित खबर के बाद हरकत में आया पंचायत विभाग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। जनपद के अकबरपुर विकासखंड के बारा गांव की बदहाल सफाई व्यवस्था और जलभराव की समस्या को लेकर 25 अप्रैल को दैनिक स्वराज इंडिया में प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कागजों में 'स्वच्छ', जमीनी हकीकत में गंदगी, बारा गांव में हालात बदतर卐 शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया।

स्वराज इंडिया
स्वराज इंडिया कानपुर देहात
कागजों में 'स्वच्छ', जमीनी हकीकत में गंदगी, बारा गांव में हालात बदतर

खबर का संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) विकास पटेल ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि खबर में गांव की मुख्य गलियों में जलभराव, टूटी सड़कों, फैली गंदगी और सफाई व्यवस्था की बदहाली को प्रमुखता से उजागर किया गया था। ग्रामीणों ने बताया था कि नालियों की सफाई न होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

समाचार प्रकाशित होने के बाद पंचायत विभाग से ग्राम पंचायत अधिकारी बोस्की शर्मा जांच की ओर तत्काल तैनात सफाई कर्मी को आवश्यक निर्देश दिए और अधिकारियों द्वारा गांव की स्थिति की जानकारी जुटाई गई तथा सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि अब लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो सकेगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि मीडिया द्वारा लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने से प्रशासनिक अमले की जवाबदेही तय होती है और समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ती है।

संदिग्ध हालात में नगदी और जेवर लेकर युवती लापता

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र के एक गांव से सोमवार को एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने गांव के ही एक युवक समेत तीन लोगों पर युवती को बहला कर ले जाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़ित पिता ने बरौर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि सोमवार भोर पहर परिवार के सभी सदस्य घर की छत पर सो रहे थे। इसी दौरान उनकी पुत्री शौचक्रिया के लिए नीचे उतरी और फिर वापस नहीं लौटी। सुबह करीब छह बजे परिवार के लोगों की आंख खुलने पर घटना की जानकारी हुई। काफी खोजबीन के बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी युवक अमित उर्फ भूरा उनकी पुत्री को फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवक के पिता राजू और माता बिटान ने भी इस घटना में सहयोग किया है। युवती घर से जेवर व करीब 50 हजार रुपये नगदी भी अपने साथ ले गई है।

बीईओ आनन्द भूषण की विदाई सपना सिंह के स्वागत में उमड़े शिक्षक

खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतीक चिन्ह भेंट करते शिक्षक महेंद्र सिंह

» मदर इंडिया जूनियर हाई स्कूल देवीपुर में हुआ भव्य समारोह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। विकासखंड मलासा के मदर इंडिया जूनियर हाई स्कूल, देवीपुर में सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी आनन्द भूषण के स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई समारोह एवं नवागत खंड शिक्षा अधिकारी सपना सिंह के स्वागत समारोह का भव्य आयोजन किया गया।कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर दोनों अधिकारियों का माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। समारोह के दौरान शिक्षकों ने स्थानांतरित खंड शिक्षा अधिकारी आनन्द भूषण के कार्यकाल की सराहना की। वहीं नवागत बीईओ सपना सिंह के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सचान ने कहा कि शिक्षक और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय से ही शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा मिल सकती है। जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष सर्वेश कटियार, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष सामरान खान तथा आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समारोह में एआरपी योगेंद्र त्रिवेदी, अश्वनी कटियार, कुलदीप सैनी एवं वीरेन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा राम नरेश कटियार, मनोज मिश्रा, संजेश कटियार, यदुनाथ सिंह, गणेश अवस्थी, नित्यानंद दोहरे, मुख्तार अहमद, अश्वनी सचान, आलोक श्रीवास्तव, यजुवेंद्र, पुष्कर पाटिल, अखिलेश कुमार, अजय प्रताप, कुशमा सचान, श्रुति सिंह, रिचा सचान, राधा देवी, प्रतिमा सिंह, रेखा, सुमन चौरसिया, उदय यादव, मनोरमा गुप्ता, नीरा सचान, महेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सैनी, पीयूष अग्निहोत्री, अजीत कुमार, गीता देवी, नवीन कुमार एवं राम खिलावन सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।

मलासा विद्यालय परिसर में मृत मिला राष्ट्रीय पक्षी मोर

भीषण गर्मी और पानी की कमी से मौत की आशंका, पोस्टमार्टम से होगा खुलासा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। मलासा गांव स्थित शहीद मूरत सिंह सविलियन विद्यालय परिसर के ब्लॉक संसाधन केंद्र के पीछे सोमवार शाम राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोर के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

ग्राम निवासी रवि सिंह ने बताया कि सोमवार शाम करीब सात बजे विद्यालय परिसर में मोर पड़ा दिखाई दिया।

पास जाकर देखने पर उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी तत्काल भोगनीपुर वन रेंज को दी गई। वन रेंजर स्वामीदीन ने बताया कि सूचना मिलते ही वनरक्षक को मौके पर भेजकर मोर के शव को कब्जे में ले लिया गया है। मोर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। प्रारंभिक तौर पर भीषण गर्मी और पानी की कमी के चलते डिहाइड्रेशन से मौत की आशंका जताई जा रही है। कानपुर देहात वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें, ताकि बेजुबान जीवों की जान बचाई जा सके।

मोबाइल टूटने से बढ़ीं दूरियां, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत

प्रेम प्रसंग में दो मौतों से दहला अकारू गांव

नाबालिग की गला रेतकर हत्या के बाद युवक ने लगाई फांसी, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के अकारू गांव में मंगलवार को प्रेम प्रसंग के चलते हुई दोहरी मौत की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक युवक ने कथित तौर पर अपनी नाबालिग प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

रोते बिलखते परिजन

मौके पर पहुंचकर जांच करते एएसपी आलोक प्रसाद

पुलिस के अनुसार मृत युवक की पहचान 25 वर्षीय शिशुपाल के रूप में हुई है, जो औरैया जिले के रामगढ़ सरैया गांव का निवासी था। वह पिछले करीब एक वर्ष से अपनी मामी सोमवती के घर अकारू गांव में रह रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली नाबालिग वर्षा देवी से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत और मेलजोल था। बताया गया कि शिशुपाल ने वर्षा को एक मोबाइल फोन उपहार में दिया था। परिजनों द्वारा मोबाइल तोड़ दिए जाने के बाद दोनों के बीच बातचीत कम हो गई थी। मंगलवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान युवक ने कथित तौर पर धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी।काफी देर तक दोनों के बाहर न आने पर परिजनों को शक हुआ। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो दोनों के शव अंदर पड़े मिले। यह दृश्य देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर मंगलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने भी मौके का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी महेश दुबे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

श्रमिकों और कंपनी के बीच 'हल्ला बोल' हुआ शांत

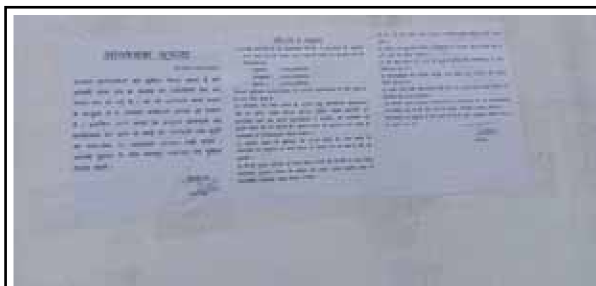

अरविन्द फुटवियर मे नोटिस चस्पा

अरविन्द फुटवियर लेदर कंपनी की हड़ताल समाप्त, एक बार फिर कामकाज शुरू

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। पिछले दो दिनों से चल रहा श्रमिकों का प्रदर्शन मंगलवार को शांत हो गया और अरविन्द फुटवियर लेदर कंपनी में एक बार फिर कामकाज शुरू हो गया। कंपनी गेट पर चस्पा किए गए नोटिस और प्रशासनिक आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धीरे-धीरे कार्यभार संभालना शुरू कर दिया।

प्राची लेदर कंपनी में भी मांगे पूरी होने की नोटिस चस्पा

हड़ताल समाप्त कर श्रमिक काम पर जाते हुए

मंगलवार सुबह से ही कंपनी परिसर में हलचल दिखाई दी, जहां लगभग 380 कर्मचारियों ने काम पर लौटकर उत्पादन कार्य शुरू किया। वहीं कंपनी के करीब 150 स्टाफ की निगरानी में कार्य सुचारू रूप से संचालित कराया गया। जानकारी के अनुसार कंपनी में लगभग 1700 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से कानपुर और कानपुर देहात के कई कर्मचारी नोटिस के अनुसार ड्यूटी पर पहुंचे। कंपनी गेट पर लगाए गए नोटिस में कर्मचारियों की मांगों और कंपनी की ओर से दिए गए जवाब को सार्वजनिक किया गया। नोटिस में वेतन भुगतान, बोनस, ईएसआई, पीएफ कटौती सहित कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। मौके पर करीब 50 पुलिसकर्मी तैनात रहे। कुछ पुलिस बल कंपनी परिसर के अंदर तो कुछ बाहर सुरक्षा व्यवस्था संभाले नजर आए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बनने पाए। सूत्रों के अनुसार हड़ताल का नेतृत्व करने वाले कुछ लोग ही सबसे पहले काम पर लौटे, जबकि कई सीधे-साधे कर्मचारी अभी भी असमंजस और डर की स्थिति में दिखाई दिए। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बाकी कर्मचारी भी धीरे-धीरे काम पर लौट आएंगे।

वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात के जैनपुर स्थित प्राची लेदर कंपनी में भी मंगलवार सुबह कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा मांगों पर सहमति जताने के बाद कर्मचारियों ने दोबारा काम शुरू कर दिया। वहां भी अकबरपुर पुलिस बल एहतियातन मौजूद रहा। फिलहाल दोनों कंपनियों में माहौल सामान्य होता दिखाई दे रहा है और श्रमिकों व प्रबंधन के बीच सहमति बनने के बाद उत्पादन कार्य दोबारा पटरी पर लौटता नजर आ रहा है।

नवीपुर जैनपुर औद्योगिक परिक्षेत्र छावनी में तब्दील, प्रशासनिक सुलह हुई फेल

स्वराज इंडिया ने हर खबर को प्रकाशित किया

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में दिखी विद्यार्थियों की प्रतिभा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकासखंड राजपुर के संविलियन विद्यालय डेराकरीमनगर में रविवार को शैक्षिक सत्र 2026-27 की पहली सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास करना रहा।विद्यालय के सहायक अध्यापक अंशुल गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में नियुक्ति के बाद से वह विद्यालय में नवाचार के तहत प्रत्येक शैक्षिक सत्र में चार सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं एवं दो विज्ञान क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल से बच्चों की बौद्धिक क्षमता, तार्किक सोच और सीखने की रुचि में निरंतर वृद्धि हो रही है।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी राजपुर अशोक सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का समय एक घंटे निर्धारित किया गया था, जिसमें कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न हल करने थे। प्रतियोगिता में कुल 35 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक एआरपी प्रदीप निरंजन एवं शोमिल बाबू की देखरेख में परीक्षा हुई। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर छात्र किशन ने प्रथम, पंकज ने द्वितीय एवं रिश्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी अशोक सिंह, एआरपी प्रदीप निरंजन, शोमिल बाबू तथा विद्यालय स्टाफ द्वारा सम्मानित किया गया।

वसूली के आरोपों से हिली लखनऊ पुलिस लाइन, दारोगा समेत 12 पुलिसकर्मी हटाए गए

सिपाही के वायरल वीडियो के बाद बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली के लगे थे आरोप

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ पुलिस में ड्यूटी लगाने के नाम पर कथित वसूली के आरोपों के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सुनील कुमार शुक्ला द्वारा वायरल किए गए वीडियो के बाद गणना कार्यालय में तैनात एक दारोगा, दो मुख्य आरक्षियों समेत कुल 12 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह नए कर्मियों की तैनाती तत्काल प्रभाव से कर दी गई है।

अमेठी के गौरीगंज निवासी सुनील कुमार शुक्ला लखनऊ पुलिस लाइन में आरक्षी के पद पर तैनात थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने और रायबरेली में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के आवेदन पास कराने के नाम पर घूस ली जाती है।

वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि गणना कार्यालय में तैनात कर्मी प्रत्येक सिपाही से ड्यूटी लगाने के एवज में दो-दो हजार रुपये की वसूली करते हैं।

मामले के तूल पकड़ने के बाद पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस उपायुक्त लाइन को सौंपी गई थी।

जांच के बीच सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित कार्यालय से 12 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके, इसलिए यह कदम उठाया गया है।सुनील कुमार शुक्ला ने पहले वीडियो के बाद तीन अन्य वीडियो भी जारी किए थे। इनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके गृह जनपद स्थित आवास पर दबिश दी गई। हालांकि बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि वहां केवल नोटिस देने के लिए टीम भेजी गई थी।

इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस लाइन की ड्यूटी व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। अब गणना कार्यालय में कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली लागू की जाएगी,

जिससे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बिना किसी भेदभाव और मानवीय हस्तक्षेप के तय हो सके।

अधिकारियों के अनुसार जांच समिति में पुलिस लाइन का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे।

एलडीए बनाएगा 900 एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आवास, सीतापुर रोड पर शुरू होगी नई योजना

लखनऊ में वासन की भारी मांग पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लिया फैसला

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। राजधानी में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बड़ी पहल की है। एलडीए द्वारा सीतापुर रोड स्थित रिया पीजी कॉलेज के पास नई आवासीय योजना विकसित की जाएगी, जिसमें करीब 900 एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों का निर्माण कराया जाएगा।प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार योजना पर लगभग 35 लाख रुपये की लागत से सर्वे एवं प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं। नई योजना के तहत क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास विकसित किए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी।

एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। योजना के अंतर्गत सड़कों, पेयजल, बिजली, पार्क और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

बताया जा रहा है कि परियोजना में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए अलग-अलग आवासीय ब्लॉक बनाए जाएंगे। इससे शहर में किफायती आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों ने एलडीए की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद परिवारों को अपना घर मिलने का सपना पूरा होगा।

सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ने जीते स्वर्ण, यूपी की महिला टीम ने बढ़ाया मान

बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता-2025-26 में देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान हुए रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया और खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की जमकर सराहना हुई।पुरुष वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में सीआरपीएफ के अंकित कुमार, भारत राघव, निखिल के और प्रवेश कुमार ध्रुव ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं असम राइफल्स के विनय, अवधेश जाट, फूलगुनी चकमा और हरी ओम ने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया।महिला वर्ग में सीआईएसएफ की प्रतिक्षा, माही सेन, आसी रावत और उर्वसी शाह ने शानदार तालमेल और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। वहीं उत्तर प्रदेश की रिचा यादव, आरती सिंह पाल, सिमरन चौधरी और नंदिनी यादव ने दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अर्जित कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह, अनुशासन और खेल भावना सभी के लिए प्रेरणास्रोत रही। उपस्थित अधिकारियों और दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को अपर पुलिस महानिदेशक राम कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर अनुभाग अतुल शर्मा तथा सेनानायक 9वीं वाहिनी पीएसी निपुण अग्रवाल द्वारा पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

» पुलिस पर मारपीट का आरोप

» जमीन विवाद से नाराज युवक ने उठाया कदम, घंटों समझाने के बाद नीचे उतरा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। शहर के नौरंगाबाद चौराहे के पास स्थित डॉ. आरसी सिंह अस्पताल के बगल में लगे मोबाइल टावर पर सोमवार को एक युवक के चढ़ जाने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए।जानकारी के अनुसार

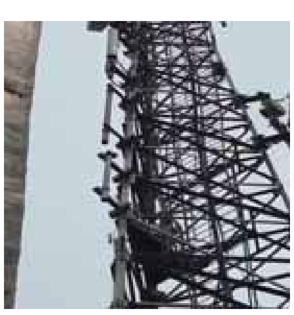

टावर पर चढ़े युवक की पहचान बिजुआ क्षेत्र निवासी दिनेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दिनेश ने एक जमीन पांच वर्ष की लीज पर ली थी। इसी जमीन को लेकर उसका जमीन मालिक से विवाद चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक विवाद के बाद दिनेश मूड़ा चौकी पहुंचा था, जहां उसने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इसी बात से नाराज होकर वह शहर पहुंचा और मोबाइल टावर पर चढ़ गया।घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी युवक को समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश में लगे रहे। काफी देर तक चले प्रयास के दौरान पुलिस लगातार युवक से बातचीत करती रही। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना रहा। पुलिस का कहना है कि युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे मामले की जांच भी कराई जाएगी।

मेटलाइफ बीमा घोटाले में बैंक अफसर गिरफ्तार

तीन करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अब तक 10 आरोपी जेल भेजे गए

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अम्बेडकर नगर। टांडा के बहुचर्चित पंजाब नेशनल बैंक शाखा टांडा मेटलाइफ बीमा धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने पीएनबी के उप शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। इससे पहले पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक सौरभ पांडेय सहित पुलिस अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।मामले में आरोप है कि पीएनबी मेटलाइफ के एजेंट उमेर अहमद ने एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा प्राप्त किसानों को बीमा योजना का झांसा देकर करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने किसानों के चेक अपने परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में जमा कराकर रकम निकलवा ली। कई किसानों

को फर्जी बीमा पॉलिसी बॉन्ड भी दिए गए। पुलिस के अनुसार इस मामले में पांच मुकदमे दर्ज हैं और विवेचना जारी है। मुख्य आरोपी उमेर अहमद, फर्जी पॉलिसी तैयार करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर तथा कई खाताधारकों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

जिस सिस्टम से लड़ाई लड़ी, अब उसी अखाड़े में उतरने की मजबूरी

अयोध्या पहुंचीं विनेश फोगाट ने कहा खिलाड़ी को वहीं जाना पड़ता है जहां खेल होता है

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। विनेश फोगाट सोमवार शाम को अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने रामलला और हनुमंत लला के दर्शन-पूजन किए। इसके बाद वह नंदिनी नगर में आयोजित नेशनल ओपन रेसलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए रवाना हुईं।मीडिया से बातचीत में विनेश फोगाट ने कहा कि ÷प्रभु राम ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। मैं रामलला का आशीर्वाद लेकर नंदिनीनगर जा रही हूं। अपने ऊपर लगे प्रतिबंध और प्रतियोगिता में खेलने को लेकर उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, खेलती हूं कि नहीं खेलती हूं।

पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह से जुड़े संस्थान में प्रतियोगिता आयोजित होने को लेकर पूछे गए सवाल पर विनेश ने कहा कि वहां जाना उनके लिए मानसिक दबाव जैसा है, लेकिन खिलाड़ी के पास विकल्प नहीं होता। उन्होंने कहा, जहां खेल होगा, खिलाड़ी को वहीं जाना पड़ता है। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने देश के लिए मेहनत की है और उन्हें एक मौका मिलना चाहिए ताकि वह फिर से मेडल जीत सकें। कारण बताओ नोटिस के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें जवाब देने का अवसर मिला है और वह अपना पक्ष रखेंगी। अयोध्या में दर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि रामलला की धरती पर सबकी कामना पूरी होती है, मेरी भी होगी।

रामनगरी को सिर्फ नारों में सम्मान, सत्ता में नहीं हिस्सेदारी!

» नौ साल की योगी सरकार में अयोध्या फिर खाली हाथ, मंत्री पद के लिए तरसते रह गए भाजपा विधायक

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जिस अयोध्या के नाम पर पूरी राजनीति चमकाई गई, जिस रामनगरी को भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी वैचारिक प्रयोगशाला बनाया, उसी अयोध्या को यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में फिर ठेंगा दिखा दिया गया। योगी सरकार के नौ साल गुजर गए, लेकिन अयोध्या का एक भी विधायक मंत्री नहीं बन पाया।

सत्ता के गलियारों में यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि आखिर रामनगरी सिर्फ चुनावी पोस्टर है या सत्ता में उसकी कोई हिस्सेदारी भी है?

चार-चार बार के विधायक रामचंद्र यादव हों, दो बार से अयोध्या सदर सीट संभाल रहे वेद प्रकाश गुप्ता हों या सक्रिय युवा चेहरा डॉ. अमित

सिंह चौहान सबके समर्थक मंत्री पद की आस लगाए बैठे थे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

भाजपा समर्थकों के बीच दबी जुबान में यह चर्चा तेज है कि राम मंदिर के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन अयोध्या को ताकत नहीं।

सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार का असर अब भी सत्ता के शीर्ष तक दर्ज है।

अंदरखाने में यह भी चर्चा है कि अयोध्या के जनप्रतिनिधि चुनाव में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा पाए, जिसकी कीमत अब राजनीतिक उपेक्षा के रूप में चुकानी पड़ रही है। विडंबना देखिए, हजारों करोड़ की परियोजनाओं से चमकाई जा रही रामनगरी के हिस्से आज भी सिर्फ भूमिपूजन, उद्घाटन और भाषण ही आ रहे हैं। मंत्री पद नहीं।रामनगरी को सिर्फ नारों में सम्मान, सत्ता में नहीं हिस्सेदारी!

जून से सभी प्रीपेड मीटर होंगे पोस्टपेड रिचार्ज के झंझट से मिलेगी मुक्ति

मुख्य अभियंता बोले, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रेसवार्ता में मुख्य अभियंता बृजेश कुमार ने घोषणा की कि जनपद में लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब चरणबद्ध तरीके से पोस्टपेड व्यवस्था में बदले जाएंगे। नई व्यवस्था जून 2026 से लागू होगी।

मुख्य अभियंता ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को रोज-रोज रिचार्ज कराने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।

एक माह बिजली उपयोग के बाद बिल जारी होगा, जिसे जमा करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद सात दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले में करीब एक लाख दस हजार स्मार्ट मीटरों का कन्वर्जन शुरू हो चुका है और सभी नए बिजली कनेक्शन भी अब पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। स्मार्ट मीटरों की शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

अयोध्या को मिलेगा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का तोहफा

» डीएम ने किया निरीक्षण, 163 करोड़ की परियोजना से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अयोध्या रामपथ पर निर्माणाधीन 300 शैय्या वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। डीएम ने निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

करीब 163.71 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह सात मंजिला अस्पताल पुराने सीतापुर आंख अस्पताल की जगह ईपीसी मोड पर तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में ओपीडी, आईसीयू, जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी सेवाओं सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अस्पताल बनने के बाद अयोध्या और आसपास के जिलों के मरीजों को गंभीर इलाज के लिए लखनऊ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

सफाई वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी, एक कर्मचारी की मौत, तीन घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। सहादतगंज फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने नगर निगम के ऑटोमेटिक स्वीपिंग वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सफाई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार कर्मचारी खून से लथपथ सड़क पर तड़पने लगे। दुर्घटना में नगर निगम कर्मचारी अजय कुमार (40) निवासी हाथरस गंभीर रूप से घायल हो गए। कैंट पुलिस उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरे कर्मचारी बृजेश सिंह की हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे में ट्रक चालक पुष्पेंद्र और क्लीनर रंजीत भी घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन से हटवाकर हाईवे पर यातायात बहाल कराया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर श्रेयस त्रिपाठी और कैंट पुलिस मौके पर पहुंच गई।

माझा जमथरा में जमीन का महाखेला!

» नजूल भूमि पर प्लाटिंग और रजिस्ट्री से उठे सवाल, करोड़ों निवेश पर मंडराया संकट

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के बाद माझा जमथरा की जमीनों में हुए बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त अब सवालों के घेरे में आ गई है। क्षेत्र में वर्षों से प्लाटिंग, रजिस्ट्री और पक्के निर्माण होते रहे, लेकिन अब संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि को नजूल बताया जा रहा है। इससे सैकड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई संकट में पड़ गई है।चर्चा है कि कई बड़े संस्थानों और प्रभावशाली लोगों ने भी यहां करोड़ों रुपये का निवेश किया। बावजूद इसके आज भी इलाके में प्रॉपर्टी डीलरों की प्लाटिंग

खुलेआम देखी जा सकती है। दूसरी ओर विकास प्राधिकरण महायोजना में इस क्षेत्र को ओपन लैंड बताता है, जहां स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि भूमि नजूल थी तो रजिस्ट्री कैसे हुई? खतौनी में नाम कैसे चढ़े? और अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सरकारी गाड़ी पर नहीं एचएसआरपी नम्बर प्लेट

अयोध्या। रुदौली तहसील में उपजिलाधिकारी के उपयोग में चल रही सरकारी गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़कों पर दौड़ती मिली, जिससे प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। आम जनता पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने वाला सिस्टम अपने ही अधिकारियों के मामले में खामोश नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यही गलती किसी आम नागरिक से हुई होती तो अब तक चालान काटकर कार्रवाई कर दी जाती। लेकिन सरकारी वाहन होने के कारण परिवहन विभाग और पुलिस दोनों मौन हैं। सोशल मीडिया पर मामला चर्चा में आने के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं? अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि खबर के बाद प्रशासन सरकारी वाहन पर एचएसआरपी लगवाएगा या मामला अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

रामायणकालीन वृक्षों की छांव में विकसित होगी रामनगरी

» नगर निगम बनाएगा उपवन, छात्रों के लिए खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नगर निगम अयोध्या अब रामायणकालीन वृक्षों से रामनगरी को हराभरा बनाने की तैयारी में जुट गया है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने समीक्षा बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-बड़े उपवन विकसित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से जैन मंदिरों के आसपास भी भूमि चिह्नित कर वृक्षारोपण कराने की योजना बनाई जा रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत छात्रों की सुविधा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। वशिष्ठ कुंड, मलिकपुर और चित्रगुप्त वार्ड सहित छात्र बहुल क्षेत्रों में स्थान चिह्नित किए जाएंगे। साथ ही छोटे तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर उनके सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया।

शांति दूत बनने का दावा, लेकिन ईरानी विमानों को दी पनाह, अमेरिकी रिपोर्ट से मचा भूचाल

पाकिस्तान की 'दोहरी चाल' बेनकाब!

अमेरिकी रिपोर्ट में दावा: युद्धविराम के बाद ईरान ने सैन्य विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेजे

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर खुद को शांति स्थापित कराने वाला मध्यस्थ बताता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे उसने ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर शरण देकर अमेरिका विरोधी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष सहयोग किया। इस खुलासे के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 8 अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने अपने कुछ सैन्य विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर स्थानांतरित कर दिया। इनमें ईरानी वायुसेना का आरसी-130 टोही विमान भी शामिल बताया गया है, जिसका उपयोग खुफिया सूचनाएं जुटाने और निगरानी अभियानों में किया जाता है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान को आशंका थी कि उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमले तेज हो सकते हैं, इसलिए उसने विमानों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू किया।

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव 28 फरवरी से लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच कई बार मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं

सामने आ चुकी हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की कथित भूमिका ने अमेरिका की रणनीतिक चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि यदि यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो पाकिस्तान की मध्यस्थता और कूटनीतिक विश्वसनीयता पर गंभीर पुनर्विचार करना पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के कुछ रक्षा अधिकारियों के पुराने बयानों को देखते हुए यह खुलासा चौंकाने वाला नहीं है।

हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि नूर खान एयरबेस घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है और वहां किसी बड़े सैन्य अभियान को छिपाना व्यावहारिक नहीं है। उनके अनुसार यह रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित और तथ्यों से परे है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान ने संघर्ष के दौरान कुछ नागरिक

- अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान पर ईरानी विमानों को शरण देने का दावा
- नूर खान एयरबेस पर आरसी-130 टोही विमान पहुंचने की बात
- अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान की तटस्थता पर उठाए सवाल
- पाकिस्तान और तालिबान दोनों ने आरोपों को बताया झूठ
- ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को 'कचरा' कहा

विमानों को अफगानिस्तान भेजा था। बताया गया कि महान एयर का एक विमान काबुल पहुंचा और ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद वहीं रोक दिया गया। बाद में उसे हेरात के पास स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि तालिबान सरकार के प्रवक्ता जैबिहुल्लाह मुजाहिद ने इन दावों को झूठ बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान किसी भी सैन्य गतिविधि का हिस्सा नहीं है।

क्या है नूर खान एयरबेस?

पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में स्थित एक रणनीतिक सैन्य ठिकाना है। यह पाक वायुसेना की महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र माना जाता है और राजधानी इस्लामाबाद के बेहद करीब होने के कारण इसकी सामरिक अहमियत बहुत अधिक है।

क्यों बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किल?

यदि अमेरिकी रिपोर्ट के दावे सही साबित होते हैं तो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि और अमेरिका के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इससे उसे कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है।

क्यों अहम है आरसी-130 विमान?

आरसी-130 ईरानी वायुसेना का विशेष टोही विमान माना जाता है। इसका उपयोग निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सैन्य सूचनाएं जुटाने के लिए किया जाता है। ऐसे विमान का किसी दूसरे देश में पहुंचना रणनीतिक संकेत माना जाता है।

ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को 'कचरा' बताते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान फिलहाल बेहद कमजोर स्थिति में है।

ईरान का रुख

ईरान ने साफ किया है कि वह परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। तेहरान का कहना है कि उसकी परमाणु गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों से जुड़ी हैं।

इस बीच युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान द्वारा भेजे गए नए प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव कचरा है और उन्होंने उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं समझी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है और मौजूदा सीजफायर अत्यंत नाजुक बना हुआ है।

दूसरी ओर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन और परमाणु तकनीक के मुद्दे पर किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ऐसे में युद्धविराम के बावजूद पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान की भूमिका संबंधी आरोपों की पुष्टि होती है तो यह पूरे क्षेत्र की कूटनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

गुवाहाटी में भव्य समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए नेता रहे मौजूद

तीसरी बार सत्ता की कमान, हिमंता बिस्वा सरमा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गुवाहाटी। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की सत्ता की कमान संभाल ली। राजधानी गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं की भी बड़ी मौजूदगी देखने को मिली।

राज्यपाल ने हिमंता बिस्वा सरमा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ कई मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समारोह के दौरान भाजपा समर्थकों में भारी उत्साह दिखाई दिया और पूरे परिसर में 'भारत माता की जय' तथा 'मोदी-मोदी' के नारों की गूंज सुनाई दी।

भाजपा नेतृत्व ने इसे असम में विकास, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर जनता की मुहर बताया। अपने संबोधन में हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा

कि उनकी सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे, निवेश, रोजगार और सीमावर्ती सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। उन्होंने असम को पूर्वोत्तर का आर्थिक केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समारोह के बाद सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि असम ने पिछले वर्षों में तेज विकास देखा है और नई सरकार इस गति को और मजबूत करेगी। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि राज्य में लगातार मिल रही जीत पार्टी के संगठन और सरकार की योजनाओं पर जनता के भरोसे को दर्शाती है।

शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए गुवाहाटी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात व्यवस्था भी बदली गई थी। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक समारोह के साक्षी बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिमंता बिस्वा सरमा की वापसी केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा की रणनीतिक मजबूती का संकेत है। पिछले

पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत

असम में लगातार सत्ता बरकरार रखना भाजपा के लिए रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। इससे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी पार्टी को राजनीतिक मजबूती मिलेगी।

विपक्ष के सामने नई चुनौती

कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के लिए यह परिणाम बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष अब संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व के सवालों से जूझता दिखाई दे रहा है।

विकास मॉडल पर जनता की मुहर

सड़क, निवेश, मेडिकल कॉलेज और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों को चुनाव में समर्थन मिला। भाजपा ने इन्हीं मुद्दों को चुनावी अभियान का केंद्र बनाया था।

शपथ ग्रहण समारोह की झलकियां

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा सरमा ने मंच पर गर्मजोशी से मुलाकात की
- पारंपरिक असमिया वाद्य यंत्रों और लोक कलाकारों ने अतिथियों का स्वागत किया
- भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडों के साथ विजय जुलूस जैसा माहौल बनाया
- मंच पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एकजुटता खास आकर्षण रही
- समारोह स्थल पर सुरक्षा के बावजूद आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी

कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे, जिनका असर चुनावी परिणामों में भी दिखाई दिया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com